संस्कृत कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

*274. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न राज्यों में संस्कृत कालेजों को अनुदान नहीं देता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) और (ख) . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जो संस्कृत कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत कालेजों की सूची में शामिल हैं और विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें आयोग द्वारा अनुदान दिए जाते हैं ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत महाविद्यालयो को जो बहुत कम सहायता आज तक दी है क्या इस संबंध में वे विचार करेंगे ? देश में अनेक महाविद्यालय संस्कृत के ऐसे हैं जो सभी शर्तें पूरी करते हैं और जिनमें अध्यापन का स्तर भी बहुत ऊंचा है । वर्तमान सरकार की नीति भी यह है कि वह संस्कृत भाषा को बढ़ावा देगी और संस्कृत के शिक्षण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करेगी । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी हिदायतें देंगे कि जो शर्तें उसने निर्धारित की हुई हैं उन्हें वह ढीला करे और इस तरह की शर्तें न रखे जिससे कि संस्कृत महाविद्यालयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े ? क्या मंत्री जी इन कड़ी शर्तों को शिथिल करने की हिदायत आयोग को देंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जो कालेज चल रहे हैं सबको बराबरी के स्तर पर देखा जाता है उनमें कोई फर्क नहीं है । सन् 75 से आठ संस्कृत महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान दे रहा है । देश में दो पूरे विश्वविद्यालय भी हैं---एक सम्पूर्णानन्द संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी और दूसरा के० एस० संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा । इनको भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग काफी सहायता दे रहा है ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मंत्री जी के उत्तर को सारे सदन ने सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि केवल आठ संस्कृत महाविद्यालयों को अनुदान मिल रहा है । यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है ? देश की सब से प्राचीन भाषा जो सचमुच देश को एकत्रित रखने की सामर्थ्य रखती है नेशनल इंटेग्रेशन में जिसका सबसे बड़ा योगदान है सारी प्राचीन निधि संस्कृत भाषा में संकलित है उस संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए महाविद्यालयों में से केवल आठ को ही देश भर में सहायता मिलती है जबकि इनकी संख्या कम से कम दो ढाई सौ होगी । केवल मध्य प्रदेश में ही इससे अधिक इनकी संख्या है । बहुत कम महाविद्यालयों को सहायता मिली हैं क्या इसका कारण यह नहीं है कि शर्तें जो रखी गई हैं वे बहुत कड़ी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जितने महाविद्यालय हैं और जहां उच्च स्तर की पढ़ाई होती है उन सबको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिना किसी भेदभाव के सहायता प्रदान करेगा ताकि संस्कृति को बढ़ावा मिल सके ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : संस्कृत की मदद के लिए शिक्षा के दफ्तर की ओर से सहायता का इंतजाम हैं । बहुत सी संस्थायें हैं जिनको 75 फीसदी भी अनुदान दिया जा रहा है । यह सही नहीं है कि संस्कृत के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता है । लेकिन कालेजों को अनुदान पाने के लिए जो शर्तें हैं उनको

उन्हें पूरा तो करना ही होगा नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी । शर्तों को सरल करने के लिए जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है उसके बारे में मैं अभी कुछ और नहीं कह सकता हूं ।

MR. SPEAKER: The question Hour is over. Short Notice Question.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: A few thousand college and university teachers are on a protest march because the new pay scales announced in 1971 for college and university teachers are yet to be implemented.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: I have put a starred question No. 272 which has been listed today. It has come in the ballot. But I have just now got a letter today saying that it has been postponed to 12th December. No reason has been given to me why this has been done. I have lost my chance now.

MR. SPEAKER: You have given notice to the Minister of Agriculture. It has been transferred to be answered by the Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation.

SHORT NOTICE QUESTION

Demands of Teachers and Students of Delhi University

+

SNQ. 3. DR. VASANT KUMAR PANDIT:
SHRI SAUGATA ROY:
SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI SAMAR GUHA:
PROF DILIP CHAKRAVARTY:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Delhi University Students' Union has sealed offices of the Vice-Chancellor, Pro-Vice Chancellor and two Deans of Colleges;

(b) whether the students allege burning of files and tampering of records containing incriminating information regarding excesses and atrocities by the authorities during the emergency period;

(c) if so, whether Government investigated into these charges and propose to institute any enquiry committee to go into the affairs of Delhi University during the emergency; and

(d) whether Government have decided to set up a separate inquiry to look into the demands of the Teachers and students?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to the information furnished by the University of Delhi, a group of about 30 students led by the President and Secretary of the Delhi University Student's Union came to the office of the Vice-Chancellor around 10-45 a.m. on November 12, 1977. Not finding the Vice-Chancellor in his office, they asked the personal staff of the Vice-Chancellor to vacate his office and also the personal staff of the Pro-Vice-Chancellor to do likewise. The Dean of Colleges and the Dean of Student's Welfare who were in their rooms, were also made to vacate their offices and all the rooms were locked by the students. However, on November 14, 1977 another group of about 60 students went to the University around 8-45 p.m., over-powered the security officer and chowkidars on duty, and broke open the rooms which had been locked earlier.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) An enquiry was made from the University of Delhi about the allegation regarding burning of files and tampering of records referred to in part (b) of the Question. The University has stated that the allegation is baseless and unfounded.

The other allegations made by the Delhi University Student's Union and the Delhi University Teachers' Association in their representations addressed to the Visitor about irregularities committed by the authorities durig the period of Emergency have been examined in this Ministry and